• शिकंजा...

मोबाइल खोलेगा क्रिप्टो करंसी ठगी के राज

शिमला : क्रिप्टो करंसी ठगी के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग का मोबाइल क्रिप्टो करंसी ठगी के राज खोलेगा। हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने क्रिप्टो करंसी ठगी मामले के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। हिमाचल पुलिस की एसआईटी पुलिस की टीम क्रिप्टो करंसी ठगी के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग के मोबाइल की व्हाट्सऐप चैट सहित अन्य जानकारी जुटाएगी। इसके बाद क्रिप्टों करंसी ठगी मामले से जुड़े ओर भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस की एसआईटी पता लगा रही है कि क्रिप्टो करंसी ठगी के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग के तार कहां-कहां जुड़े हैं। क्रिप्टो करंसी ठगी के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग के जरिए पुलिस टीम क्रिप्टो करंसी ठगी के मेन आरोपी सुभाष का भी पता लगाएगी। पुलिस की टीम ने आरोपी मिलन गर्ग को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। मिलन गर्ग को गुरुवार को शिमला की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मिलन गर्ग को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। मिलन गर्ग

मुख्य आरोपी सुभाष का सारा काम देखता था।

ठगी मामले की नेटवर्किंग से लेकर वेबसाइट और बाकी का ऑनलाइन काम मिलन गर्ग ही संभालता था। मिलन गर्ग उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। लोगों से करोड़ों रुपए ठगने के बाद मिलन गर्ग भी दुबई चला गया था। पुलिस आरोपी पर नजर रखे हुए थी। उधर, आईजी अभिषेक दुल्लर का कहना है कि पुलिस ने क्रिप्टो करंसी ठगी मामले के मास्टरमाइंड मिलन गर्ग को अदालत ने आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने आदेश दिए हैं। आईजी अभिषेक दुल्लर ने बताया कि आरोपी मिलन गर्ग का मोबाइल जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। आरोपी के मोबाइल से करोड़ों की इस ठगी मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। प्रदेश में करीब एक लाख से अधिक लोगों को ठगा है। क्रिप्टो रैकेट में शातिरों ने करीब अढ़ाई लाख आईडी बनाकर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर प्रदेश की जनता को करोड़ों का चुना लगाया है।

• संपादकीय...

प्रकृति का संतुलन

विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नये आविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज का मानव प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्राकृतिक संतुलन को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से जहां प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी और प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण न केवल मानव जाति को बल्कि पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणियों को ऐसे वातावरण में धकेल दिया है जहां स्वस्थ जीवन की मात्र कल्पना कर सकते है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने और धरती के श्रृंगार के लिए पौधा रोपण करना बहुत आवश्यक है। धरती पर जितने ज्यादा पेड़-पौधे होंगे। वातावरण उतना ही शुद्ध रहेगा और अच्छी बरसात होगी। हर व्यक्ति को एक-एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेना चाहिए। पेड़ पौधों का प्रकृति से अटूट बंधन है। हरियाली से स्वच्छ वातावरण बनता है। इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है और यह हमारे जीवन का आधार हैं। पौधा रोपण महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। आज इंसान स्वार्थ के लिए दिन-प्रतिदिन हरे भरे पेड़ों को काट रहा है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। अगर समय रहते जंगलों को नहीं बचाया गया और पौधा रोपण को प्राथमिकता नहीं दी गई तो आने वाले समय में शुद्ध हवा और स्वच्छ वातावरण मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम प्रकृति के नियमों की अवहेलना करेंगे और प्रकृति के संसाधनों का अनुचित दोहन करेंगे तो प्रकृति भी हमें माफ नहीं करेगी।

■ **अनल पत्रवाल**
संपादक, हिमाचल अभी अभी

आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें

❖ वेतन आयोग के एरियर का 9000 करोड़ रुपए बकाया

● पंकज/शिमला

आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों से घिरी हिमाचल सरकार को अब 16वें वित्तायोग का सहारा है। हिमाचल सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में बढ़ोतरी की शिद्दत से जरूरत है। यदि 16वें वित्तायोग ने उदार आर्थिक सहायता की सिफारिश नहीं की, तो हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का आर्थिक संकट गहरा हो जाएगा। इस समय नए वेतन आयोग के एरियर का ही 9000 करोड़ रुपए बकाया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तायोग के समक्ष अपने भाषण की जो लिखित कॉपी रखी थी, उसमें पेज नंबर 8 पर ये आग्रह किया था कि राज्य को मदद के लिए एकमुश्त प्रावधान किया जाए।

कारण गिनाते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पॉइंट नंबर 14 पर कहा था -(एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। प्रदेश सरकार छठे वेतन आयोग के एरियर अभी तक नहीं दे पाई है। यह बकाया राशि लगभग नौ हजार करोड़ रुपए है। इस बारे में अलग-अलग विभागों से संबंधित अदालतों के आदेश भी आ रहे हैं कि सारा एरियर ब्याज सहित दिया जाए। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे आदेश दिए हैं। हमने खर्चों के अनुमान में इस एरियर को आगामी पांच साल में किश्तों में देने का प्रस्ताव किया है, लेकिन अदालतों के आदेशों और कर्मचारियों व पेंशनर्स की अपेक्षाओं को देखते हुए लगता है कि यह देनदारी 2026-27 में ही चुकानी होगी। इसके लिए एकमुश्त प्रावधान किया जाना जरूरी है।)

वित्तायोग की सिफारिश पर राज्य सरकारों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है। चौदहवें व पंद्रहवें वित्तायोग से मिली ग्रांट माकूल थी और उससे राज्य सरकार के वेतन व पेंशन का खर्च काफी हद तक निकल जाता था, लेकिन ये ग्रांट अब निरंतर घटती जा रही है। इसका कारण वित्तायोग के राजस्व घाटा अनुदान को टेपर करना है। टेपर यानी हर साल तय फार्मूले के तहत ग्रांट में कटौती होती चली जाती है। इसी कटौती के कारण इस वित्त वर्ष यानी 2024-25 में जो ग्रांट 6258 करोड़ रुपए सालाना है, वो घटकर 3257 करोड़ रह जाएगी। यानी हर महीने हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर केंद्र से 270 करोड़ रुपए से कुछ अधिक महीने में जारी होंगे। इधर, वेतन व पेंशन का खर्च 1500 करोड़ रुपए महीना के करीब है। ऐसे में सरकार को वेतन व पेंशन का जुगाड़ करने में ही पसीने छूटेंगे। एरियर चुकाना तो दूर की बात है। सोलहवें वित्तायोग की सिफारिशों के बाद केंद्र से जो राशि मिलनी है, उसके लिए भी वर्ष 2026 का इंतजार करना होगा। इस वित्तायोग का कार्यकाल 2026 से 2031 तक का है। पंद्रहवें वित्तायोग का कार्यकाल 2021 से 2026 तक का है।

हिमाचल की पूर्व जयराम सरकार के समय तक वेतन व पेंशन के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से काफी राहत मिलती रही थी। कारण ये था कि उस समय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की रकम पर्याप्त थी। पंद्रहवें वित्तायोग की बात करें तो उसकी सिफारिश पर हिमाचल को 2021-22 में 10249 करोड़ रुपए सालाना ग्रांट के तौर पर मिले थे। उस समय वेतन व पेंशन का खर्च भी एक हजार करोड़ रुपए महीना से कम था। ऐसे में करीब 850 करोड़ रुपए हर महीने ग्रांट के तौर पर मिल जाते थे और वेतन आदि का खर्च पूरा करने में आसानी होती थी।

वर्ष 2022-23 में ये ग्रांट 9377 करोड़ रुपए सालाना थी। फिर 2023-24 में ये 8058 करोड़ रुपए हुई। अगले वित्त वर्ष 2024-25 में ये 6258 करोड़ रह गई। यानी मौजूदा वित्त वर्ष में ये ग्रांट 6258 करोड़ रुपए है। अगले वित्त वर्ष में ये टेपर होकर 3257 करोड़ रुपए रह जाएगी।

नए वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। हालांकि उन्हें एरियर नहीं मिला है, लेकिन वेतन की बढ़ोतरी ही इतनी है कि सरकार का खजाना उसे संभाल नहीं पा रहा है। वित्तायोग के समक्ष रखे गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार को सिर्फ और सिर्फ वेतन के लिए ही 15862 करोड़ रुपए चाहिए। पेंशन के लिए अलग से 10800 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यानी वेतन व पेंशन का खर्च मिलाकर 26722 करोड़ रुपए होगा। वहीं, राजस्व घाटा अनुदान सिर्फ 3257 करोड़ रुपए रह जाएगा। इस तरह राज्य सरकार को वेतन व पेंशन का खर्च पूरा करने के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना होगा। आलम ये है कि अब राज्य सरकार की सारी उम्मीदें सोलहवें वित्तायोग की सिफारिशों पर टिकी हुई हैं।

कारण गिनाते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पॉइंट नंबर 14 पर कहा था -(एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। प्रदेश सरकार छठे वेतन आयोग के एरियर अभी तक नहीं दे पाई है।

यह बकाया राशि लगभग नौ हजार करोड़ रुपए है। इस बारे में अलग-अलग विभागों से संबंधित अदालतों के आदेश भी आ रहे हैं कि सारा एरियर ब्याज सहित दिया जाए। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे आदेश दिए हैं...

• उपलब्धि...

किन्नौर में कडू की खेती

रिकांगपिओ : जिला किन्नौर में बारह मौसमी जड़ी-बूटी कडू की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजा ने कसरत शुरू कर दी है और आने वाले समय में जरूर रंग लाएगी। इस औषधीय खेती के लिए वन परिक्षेत्र निचार के अंतर्गत निगुलसरी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वानिकी परियोजना के जैव विविधता विशेषज्ञ डॉ. एसके काप्टा ने की। उन्होंने यहां के लोगों को कीमती जड़ी-बूटी की खेती के लिए जागरूक किया। गौरतलब है कि यह प्रजाति अल्पाइन हिमालय में 27 सौ से 5 हजार मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। इसके लिए जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं। डॉ. एसके काप्टा ने कहा कि कडू तीन साल बाद तैयार होता है। वर्तमान में इसकी कीमत 12 सौ से 15 सौ रुपये प्रति किलो है। ऐसे में किसान इसकी खेती कर अपनी आर्थिकी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। डॉ. एसके काप्टा ने ग्राम वन विकास समिति निगानी, निगुलसरी, तरांडा और थाच के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे लोगों को अवगत करवाया कि जाइका वानिकी परियोजना जल्द ही निचार वन परिक्षेत्र में कडू की खेती के लिए 50 किसानों का एक ग्रुप तैयार करेगी।

• मकान और गोशाला राख...

हमीरपुर : जिले के उपमंडल भोरंज के अंतर्गत भुक्कड़ पंचायत के गांव बैरी भटां में शुक्रवार अल सुबह करीब 4:30 बजे तीन कमरों का स्लेटपोश मकान, गोशाला जलकर राख हो गए। ग्राम पंचायत भुक्कड़ के प्रधान किशोर चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव बैरी भटां के तीन भाइयों सुरेश कुमार, कमलेश कुमार व राकेश कुमार का पुराना रिहायशी मकान-गोशाला अचानक आग लगने से जल गए। उन्होंने बताया की कमलेश कुमार का परिवार आईआरडीपी से सबंधित है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है।